# The Research Dialogue

An Online Quarterly Multi-Disciplinary Peer-Reviewed / Refereed Research Journal

ISSN: 2583-438X

Volume-04, Issue-01, April-2025

www.theresearchdialogue.com



"भारत-अमेरिका संबंध: बाइडेन प्रशासन की 'इंडो-पैसिफिक' नीति के विशेष संदर्भ में"

डॉ. तेज प्रताप सिंह,

सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, गंजडुंडवारा महाविद्यालय, गंजडुंडवारा,कासगंज

#### सार

प्रस्तुत शोध पत्र में बाइडेन प्रशासन के दौरान भारत-अमेरिका संबंध में हुई प्रगित एवं चुनौतियों का अध्ययन इंडो-पैसिफिक नीति के विशेष संदर्भ में किया गया है। 2005 के बाद से दोनों देशों के मध्य संबंध निरंतर प्रगाढ़ हो रहे हैं। बाइडेन प्रशासन के दौरान इन संबंधों में और प्रगित हुई है, और इसमें इंडो - पैसिफिक क्षेत्र की प्रमुख भूमिका रही है। बाइडेन प्रशासन का इस क्षेत्र में चीन के वर्चस्व को नियंत्रित करना प्राथमिकताओं में था और भारत भी इस क्षेत्र में चीन के वर्चस्व को नियंत्रित करना चाहता है जो भारत के राष्ट्रहित है, इसलिए इस क्षेत्र में भारत, अमेरिका का एक प्रमुख सहयोगी बन गया है। यद्यपि कुछ मुद्दों पर मतभेद भी बने रहे जैसे व्यापार के मुद्दे एवं रूस के साथ रक्षा संबंध इत्यादि।

प्रमुख शब्दावलियां:- भू - आर्थिक, भू -सामरिक, शक्ति - सन्तुलन, रणनीतिक स्वायत्तता।

#### प्रस्तावना

बीसवी शताब्दी मे भारत-अमेरिका संबंधों का इतिहास देखें तो दोनों देशों के बीच परस्पर संदेह और दूरी का वातावरण रहा। हालांकि, 21वीं सदी की शुरुआत और विशेष रूप से 2005 के भारत-अमेरिका नगरिक परमाणु समझौते के बाद दोनों देशों के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई। ओबामा, ट्रंप और अब बाइडेन प्रशासन के दौरान यह रणनीतिक साझेदारी और गहरी होती गई है, जिसमें इंडो-पैसिफिक क्षेत्र, सहयोग का एक प्रमुख केंद्र बिंदु बन गया है।

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र, हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक फैला है। समकालीन विश्व राजनीति में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक प्रमुख समुद्री व्यापार मार्ग है और इस क्षेत्र में संसार की लगभग 60% आबादी रहती है। इस क्षेत्र की भू-आर्थिक और भू-सामरिक महत्ता ने इसे अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों का केंद्र बना दिया है। चीन की आक्रामक विस्तारवादी नीति ने इस क्षेत्र में भारत, अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया को आपस में सहयोग के लिए प्रेरित किया है। राष्ट्रपित जो बाइडेन ने इंडो-पैसिफिक को अपनी विदेश नीति में प्राथमिकता में रखा। फरवरी 2022 में जारी 'इंडो पेसिफिक स्ट्रेटजी ऑफ़ द यूनाइटेड स्टेट्स' दस्तावेज में अमेरिका ने इस क्षेत्र को 'स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी, सुरक्षित और समृद्ध' बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। बाइडेन का मानना है कि वैश्विक राजनीति का भविष्य इस क्षेत्र में शक्ति-संतुलन की प्रकृति पर निर्भर करेगा इसलिए अमेरिका का उद्देश्य इस क्षेत्र में चीन को प्रति संतुलित करने के साथ ही क्षेत्रीय स्थिरता, समुद्री स्वतंत्रता और आर्थिक सहभागिता को बढ़ावा देना है। भारत,अमेरिका की इस रणनीति में एक प्रमुख साझेदार के रूप में उभरा है। अमेरिका की इंडो-पैसिफिक नीति का भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' तथा 'इंडो-पेसिफिक ओशन इनीशिएटिव' के साथ में सामंजस्य दिखाई देता है। बाइडेन प्रशासन ने भारत के साथ रणनीतिक, रक्षा, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को और अधिक गित देकर भारत को "प्रमुख रक्षा साझेदार" की मान्यता को और मजबूत किया है।

बाइडेन प्रशासन ने फरवरी 2022 में प्रकाशित दस्तावेज 'इंडो पेसिफिक स्ट्रेटजी ऑफ़ द यूनाइटेड स्टेट्स' के माध्यम से इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को अमेरिकी विदेश नीति की "मुख्य धुरी" के रूप में पुनः परिभाषित किया और इस क्षेत्र में अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया। यह नीति अमेरिका की उस दीर्घकालिक रणनीति का विस्तार है जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में स्वतंत्रता, खुलेपन, साझेदारी, और स्थिरता को बनाए रखना है। अमेरिका का प्रयास है कि चीन, इस क्षेत्र के देशों की संप्रभुता और समुद्री स्वतंत्रता का उल्लंघन न कर सके। अतः अमेरिकी नीति में विवादों के शांतिपूर्ण समाधान,अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून का सम्मान और दक्षिण चीन सागर में नौवहन की स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी गई है। अमेरिकी प्रशासन का उद्देश्य इस क्षेत्र में अपने सहयोगियों भारत,दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम जैसे देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना एवं सहयोगियों की संख्या को बढ़ाना है, जिससे संतुलित क्षेत्रीय व्यवस्था स्थापित की जा सके। बाइडेन प्रशासन क्वॉड को एक सिक्रय एवं मजबूत संगठन बनाना चाहता है, इसलिए इसमें सुरक्षा के साथ ही जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा,आपदा प्रबंधन, टीका निर्माण एवं नवीन तकनीकों जैसे विषयों को शामिल कर बहुआयामी बनाया गया है, जिससे क्वॉड को मजबूती मिल सके। क्वॉड के अतिरिक्त बाइडेन प्रशासन ने 2022 में इंडो - परिफ़िक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लॉन्च किया, जिसमें भारत समेत 14 देशों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य डिजिटल व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा, कार्बन न्यूट्रिलटी और भ्रष्टाचार-विरोध जैसे मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देना है।

भारत, अपनी भौगोलिक स्थिति, आर्थिक क्षमता और रणनीतिक दृष्टिकोण के कारण इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शिक्त बन गया है। बाइडेन प्रशासन की इंडो-पैसिफिक नीति में भारत एक "महत्वपूर्ण और विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार" है, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, समुद्री सुरक्षा, और बहुपक्षीय सहयोग में विश्वास करता है। भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी', का उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया, कोरिया ऑस्ट्रेलिया और जापान, जैसे देशों के साथ आर्थिक, राजनीतिक, और सुरक्षा सहयोग को सुदृढ़ करना है। इसके साथ ही भारत 'इंडो पेसिफिक ओशन इनीशिएटिव' के द्वारा समुद्री सुरक्षा, पारिस्थितिकी संरक्षण, और व्यापार संपर्कों को बढ़ावा देकर इस क्षेत्र में केवल एक भागीदार ही नहीं, बल्कि नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाने के लिए भी तैयार है। भारत, क्वाड के चार प्रमुख सदस्य देशों में से एक है। क्वाड की नियमित बैठको, नौसैनिक अभ्यास, और बहुस्तरीय संवाद में भारत की सिक्रय भूमिका रहती है। इस मंच के

माध्यम से भारत, जापान अमेरिका, और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा,, स्वास्थ्य, और आपूर्ति श्रृंखला स्थिरता जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहा है। अमेरिका और अन्य साझेदार देशों के साथ मिलकर भारत समुद्री डकैती, तस्करी और अवैध गतिविधियों के खिलाफ निगरानी तंत्र विकसित कर रहा है। भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री निगरानी और सूचना के लिए 'इनफॉरमेशन फ्यूजन सेंटर' की स्थापना की है, जो इस क्षेत्र में समुद्री निगरानी और सूचना साझाकरण का केंद्र बन चुका है। भारत बिम्सटेक, आसियान, और ईस्ट एशिया सम्मिट जैसे मंचों के माध्यम से इंडो-पैसिफिक में एक संतुलित और बहुपक्षीय व्यवस्था के निर्माण में योगदान दे रहा है।

बाइडेन प्रशासन के दौरान भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी ने नई गहराइयाँ प्राप्त की हैं। दोनों देशों ने न केवल सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ किया है, बल्कि उभरती तकनीकों, ऊर्जा, स्वास्थ्य और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला जैसे क्षेत्रों में भी परस्पर सहयोग का विस्तार किया है। यह साझेदारी केवल द्विपक्षीय हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की स्थिरता, कानून के शासन, और मुक्त नौवहन की सुरक्षा से भी जुड़ी हुई है। भारत और अमेरिका के बीच चार प्रमुख आधारभूत रक्षा समझौते पूरे हो चुके हैं:

- 1. लेमोए (लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ़ एग्रीमेंट) सैन्य अड्डों तक पारस्परिक पहुँच के लिए।
- 2. कॉमकासा (कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट) सैन्य संचार के लिए सुरक्षित चैनल।
- 3. बी ई सी ए (बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट) भू-स्थानिक डाटा साझा करने के लिए।
- 4. <mark>जी एस ओ</mark> एम आई ए (जनर<mark>ल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इनफॉरमेशन एग्रीमेंट) संवेदनशील सैन्य जानकारी क<mark>ी सुरक्षा हेत</mark>ु।</mark>

इन समझौतों के माध्यम से दोनों देशों की सेनाओं के बीच अंतर-संचालन और सामिरक विश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। भारत और अमेरिका नियमित रूप से 'मालाबार' नौसैनिक अभ्यास और 'बज्र प्रहार' जैसे युद्धाभ्यासों में भाग लेते हैं। इन अभ्यासों का उद्देश्य संयुक्त संचालन क्षमता को बेहतर बनाना और क्षेत्रीय खतरों से सामूहिक रूप से निपटना है। भारत, 'इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क' के 14 सदस्य देशों में शामिल है। इस मंच के माध्यम से भारत और अमेरिका डिजिटल व्यापार, आपूर्ति शृंखला सुरक्षा, हिरत अर्थव्यवस्था और कर-पारदर्शिता जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। 2023 में स्थापित 'इंडिया - यूएस इनीशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज' का उद्देश्य सेमीकंडक्टर निर्माण, रक्षा नवाचार कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5जी/6जी, और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग कर चीन के तकनीकी वर्चस्व को संतुलित करना और विश्वसनीय आपूर्ति शृंखला तैयार करना है। जी20, संयुक्त राष्ट्र, और अन्य बहुपक्षीय संस्थानों में भारत और अमेरिका के दृष्टिकोण अक्सर समान होते हैं। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, वैश्विक स्वास्थ्य, और लोकतांत्रिक शासन जैसे मुद्दों पर दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं।

भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के विकास में **चीन** एक निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। बाइडेन प्रशासन की इंडो-पैसिफिक नीति और भारत की 'एक्ट ईस्ट पालिसी ' तथा 'इंडो-पैसिफिक ओशन इनीशिएटिव' जैसी पहलों का एक साझा उद्देश्य है— चीन की बढ़ती आक्रामकता का रणनीतिक संतुलन। चीन की आर्थिक, सैन्य और तकनीकी शक्ति में वृद्धि ने न केवल अमेरिका बल्कि भारत के लिए भी एक चुनौती प्रस्तुत की है। चीन दक्षिण चीन सागर पर एकतरफा दावा करता है और लगातार उस क्षेत्र में कृत्रिम द्वीप निर्माण व सैन्यीकरण कर रहा है। अमेरिका इसे अंतरराष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन के रूप में देखता है, जबिक भारत इस क्षेत्र में मुक्त नौवहन और व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा में रुचि रखता है। इस साझा चिंता ने दोनों देशों को समुद्री सुरक्षा में मिलकर कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। 'बीआरआई' के माध्यम से चीन रणनीतिक अवसंरचना परियोजनाओं द्वारा छोटे देशों को कर्ज-जाल में फँसाकर अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है, इसलिए भारत और अमेरिका दोनों इस परियोजना की पारदर्शिता और देशों की संप्रभुता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंतित हैं और इसके विकल्प के रूप में दोनों देश जी 7 के 'बिल्ड बैक बेटर वर्ड' और 'इंडिया- मिडल ईस्ट- यूरोप इकोनामिक कॉरिडोर' को बढ़ावा दे रहे हैं।

2020 के गलवान संघर्ष के दौरान अमेरिका ने भारत की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करते हुए खुले रूप से चीन की विस्तारवादी नीति की आलोचना की। इसके पश्चात भारत ने क्वाड और अन्य मंचों पर अमेरिका के साथ अपने रणनीतिक जुड़ाव को और सुदृढ़ किया। चीन की तकनीकी कंपनियाँ वैश्विक साइबर सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी हैं। भारत और अमेरिका ने मिलकर विश्वसनीय तकनीकी इकोसिस्टम बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं। इसमें 5जी -6जी , सेमीकंडक्टर, क्वांटम और कृतिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। भारत और अमेरिका क्वाड को एक सकारात्मक, लोकतांत्रिक और समावेशी मंच के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और विकास है – न कि चीन का विरोध मात्र। लेकिन चीन ने प्रारंभ से ही इसे एक 'एशियाई नाटो' करार देते हुए विरोध किया है।

### निष्कर्ष

बाइडेन प्रशासन के दौरान भारत-अमेरिका संबंधों ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बीच उल्लेखनीय प्रगित की है। दोनों देशों ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, रणनीतिक हितों, और क्षेत्रीय स्थिरता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी साझेदारी को बहुआयामी बनाया है। इंडो-पैसिफिक नीति के तहत अमेरिका की सिक्रयता और भारत की स्वतंत्र लेकिन साझेदारी-प्रधान विदेश नीति ने एक संतुलित सहयोग मॉडल प्रस्तुत किया है, जो चीन के वर्चस्ववादी दृष्टिकोण के लिए एक व्यवहारिक प्रतिसंतुलक बन कर उभरा है। यद्यपि, इस साझेदारी के समक्ष कुछ चुनौतियाँ भी बनी हुई हैं – जैसे भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की नीति, रूस के साथ भारत के पारंपरिक रक्षा संबंध, और व्यापारिक मुद्दों पर मतभेद।

### संदर्भ सूची:-

- Singh, Tej Pratap, Bharat America Sambandh: 2009 se vartman tak, 2022
- Pant, Harsh V., and Happymon Jacob. The US and India: A Relationship in Transition. ORF Occasional Paper, 2021.

- U.S. Indo-Pacific Strategy (2022) The White House. Retrieved from https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/11/fact-sheet-indo-pacific-strategy-of-the-united-states
- Quad Joint Leaders' Statements (2021–2023) Ministry of External Affairs, India. Retrieved from https://www.mea.gov.in
- India-U.S. Initiative on Critical and Emerging Technology (iCET), 2023 U.S. Department of State.

  Retrieved from https://www.state.gov/india-u-s-initiative-on-critical-and-emerging-technology
- Brewster, David. India's Ocean: The Story of India's Bid for Regional Leadership. Routledge, 2014.



# THE RESEARCH DIALOGUE

Peer-Review

An Online Quarterly Multi-Disciplinary

Peer-Reviewed / Refereed National Research Journal

ISSN: 2583-438X

Volume-04, Issue-01, April-2025

www.theresearchdialogue.com

Certificate Number April-2025/04

Impact Factor (RPRI-4.73)

# **Certificate Of Publication**

This Certificate is proudly presented to

डॉ. तेज प्रताप सिंह

for publication of research paper title

"भारत-अमेरिका संबंध: बाइडेन प्रशासन की 'इंडो-पैसिफिक' नीति के विशेष संदर्भ में"

Published in 'The Research Dialogue' Peer-Reviewed / Refereed Research Journal and

E-ISSN: 2583-438X, Volume-04, Issue-01, Month April, Year-2025.

Dr. Ne<mark>eraj Yadav</mark> Executive Chief Editor

Dr. Lohans Kumar Kalyani Editor-in-chief

**Note:** This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at <a href="https://www.theresearchdialogue.com">www.theresearchdialogue.com</a>

INDEXED BY





















